

हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
05 अगस्त 2026, समय 18:10

मुख्य समाचार

- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल शासन, कौशल विकास और डाटा आधारित प्रशासन पर चर्चा की।
- लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेन्स विधेयक 2026 पारित किया, जिससे बैंकों के रिकार्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकेगी।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परसों ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे।
- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति से जुड़े दो विनियमों में संशोधन किया – अनुबंधित मांग से दस प्रतिशत तक अधिक बिजली उपयोग करने पर सरचार्ज नहीं लगेगा।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने हरियाणा में सीवर कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल शासन, कौशल विकास और डेटा-आधारित प्रशासन पर चर्चा की।

बैठक के दौरान विश्व बैंक के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 19 से 22 अक्टूबर तक कोरिया में आयोजित होने वाले कोरिया डिजिटल समिट में विश्व बैंक द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से विकसित एआई सैंडबॉक्स को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक से हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं विकास परियोजना को शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि इसके तहत प्रस्तावित एआई गुरुकुल युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करेगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लिए समर्पित एआई मॉडल तैयार करने का सुझाव भी रखा। उन्होंने कहा कि यह मॉडल राज्य के कानूनों, नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं को

समझते हुए अधिकारियों को त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा और नागरिकों को अधिक तेज, सरल एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक से प्रदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एयर क्वालिटी डिजीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने में सहयोग का अनुरोध भी किया। उन्होंने विश्व बैंक से विभिन्न सरकारी विभागों की चुनौतियों का अध्ययन कर उनके सरल, व्यावहारिक और किफायती तकनीकी समाधान विकसित करने में भी सहयोग मांगा।

लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक-2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया।

इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परसों 7 अगस्त को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे।

खेल, राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। जिसमें खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रात्री भोज पर खिलाड़ियों के साथ खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण को लेकर चर्चा भी करेंगे।

श्री गौतम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने सात स्वर्ण,, दो रजत और एक कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते हैं उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को प्रोत्साहन स्वरूप साढ़े सात लाख रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति से जुड़े दो महत्वपूर्ण विनियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अनुबंधित मांग से 10 प्रतिशत तक अधिक बिजली उपयोग करने पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। जबकि पहले स्वीकृत लोड से 5 प्रतिशत से अधिक मांग होने पर भी बिजली शुल्क पर 25 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जा रहा था।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह संशोधन विशेष रूप से उन औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी साबित होगा, जिनके यहां मौसमी, उत्पादन संबंधी अथवा अन्य अस्थायी कारणों से बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार यदि मांग 110 से 115 प्रतिशत के बीच रहती है तो कुल बिजली शुल्क पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा, जबकि 115 प्रतिशत से अधिक मांग होने पर पहले की तरह 25 प्रतिशत सरचार्ज लागू रहेगा। संशोधित नियमों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता बिना वोल्टेज स्तर बदले अपना लोड कम कराता है तो उसे केवल निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये होगी।

संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने चर्चा के बाद इस विधेयक को लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा ने इसे सोमवार को ही पास कर दिया था।

इस विधेयक में सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है।

इस साल मई में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा के निर्देश पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने हरियाणा में सीवर कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। समिति में मुख्यालय के मुख्य अभियंता, संबंधित जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी सर्किल के अधीक्षण अभियंता तथा संबंधित मंडल के कार्यकारी अभियंता शामिल होंगे।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि समिति अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों का समय-समय पर दौरा करेगी और और मौके पर जाकर सीवर कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा मानकों, सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करेगी ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की कमी सामने आती है तो उसे तत्काल दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। श्री गंगवा ने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों अथवा एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रदेशव्यापी कलश यात्रा का आज पानीपत में स्वागत किया गया।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने स्वागत द्वार बनाकर जगह-जगह पुष्प वर्षा, आरती और जयघोष के साथ कलश यात्रा का अभिनंदन किया गया। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में भजन-कीर्तन और गुरु रविदास के संदेशों का प्रचार किया गया।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य गुरु रविदास महाराज के समानता, भाईचारे, सामाजिक समरसता और मानव सेवा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से कलश गांव-गांव भेजे जाएंगे ताकि लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले।

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए लिंक अधिकारी नामित किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के पद के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव को तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ओएसडी को लिंक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

इसी प्रकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को लिंक अधिकारी तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ओएसडी को लिंक अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है।

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे या चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व अपने लिंक अधिकारी को इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
